ISBN-978-81-89740-97-9

मानव अधिकार एवं जनचेतना

(राष्ट्रीय संगोष्ठी)

दिनांक 10 दिसंबर 2016

प्रायोजक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

डॉ. संध्या टिकेकर
प्राचार्य/संरक्षक

डॉ. निशा जैन
संपादक

डॉ. उमा लवानिया
सह संपादक

शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना
नैक प्रत्यायित 'बी' ग्रेड

मानवाधिकारों की जन चेतना में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

डॉ. दीपक मोदी
अतिथि विद्वान
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश

21 वीं सदी लोकतंत्र, मानवाधिकारों और बाजार की सदी है तथा एक ओर भूमंडलीकरण तथा दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण इसकी विषेशता है। षक्तिका केन्द्र बदल रहा है तथा बड़ी हद तक इसका कारण लोकतंत्र और 'संगठित' जीवन की मांग है। आज मानव को सभ्य बनना है तो जरूरी है कि साहचर्य की कला का उसी अनुपात में विकास और सुधार हो जिस अनुपात जीवन की दषाओं में समानता बढ़े। 'साहचर्य' तथा ''जीवन की दषाओं की समानता'' पर अगर जोर दिया जा रहा है तो इसका मुख्य कारण गैर सरकारी संगठन है जिन्होंने पता लगाया कि खुद के मामलों में जनता की सुनिष्चित 'भागीदारी' से ही उपर्युक्तदोनों बातें संभव है। गैर सरकारी संगठन, निजी, अलाभकारी पेषेवर संगठन हैं जिनका लोक-कल्याण के लक्ष्यों से जुड़ा एक स्पश्ट कानूनी चरित्र होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में वे राज्य के प्रयासों के अच्छे पूरक साबित होते हैं। विधान और लोक-नीति पर गैर-सरकारी संगठन सार्थक प्रभाव डालते हैं। वास्तव में वे सरकारी और गैर सरकारी मंचों पर जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी के सबसे करीबी रूप है। कुछ तो आगे बढ़कर संघर्श के लिए राजनीतिक षक्ति प्रदान करते हैं। मिसाल के तौर पर भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की अनेक मिसालें दी जा सकती हैं जिन्होंने मनुश्यों के विकास पर एक नैतिक और दार्षनिक प्रभाव छोड़ा है।

गैर सरकारी संगठन लोगों के छोटे-छोटे समूह हैं जो मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए लड़ते हैं। गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के दबाब के कारण यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की गई है कि देष दूसरे देषों द्वारा मानवाधिकारों के हनन की छानबीन और निगरानी करने में असफल रहे हैं। ऐसे दबावों के अंतर्गत ये देष 'मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने तथा अन्तर्राश्ट्रीय संधियों और मानदंडों के निर्धारण से हिचकते हुए आगे बढ़े और मानवाधिकारों को सरंक्षण देने की बात करने लगे जिसमें क्रियान्वयन और व्यवहार पर जोर दिया जाता था। स्पश्ट है कि मानवाधिकार समुदाय भी मानवाधिकार आंदोलन के प्रसार के साथ बढ़ा है, और यह आंदोलन भी अधिकतर उन सजग और सावधान लोगों के संगठित दलों/समूहों की उपज हैं जो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं।

मुख्य षब्द - लोकतंत्र, मानव अधिकार, गैर सरकारी संगठन, जन भागीदारी, मानव अधिकार संरक्षण

ऐसे गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठन स्थानीय, प्रांतीय, राश्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राश्ट्रीय भी हो सकते हैं। जैसे पीपुल्स वाच पीयूसीएल और पी यू डी आर भारत में राश्ट्रीय समूहों के उदाहरण हैं। एमनेस्टी इंटरनेषनल, ह्यूमन राइट्स इंटरनेट (कनाडा) और एफ आई ए एन (फूड फर्स्ट इनफार्मेषन ऐंड एक्षन नेटवर्क) विश्व स्तर पर सक्रिय है जबकि कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिषिएटिव, फोरम एषिया (सिंगापुर) ह्यूराइट्स (ओसाका) तथा दक्षिण अमेरिका में फैडफैम (ब्यूनस आयर्स) क्षेत्रीय संगठनों के उदाहरण हैं। मानवाधिकारों की सार्थकता को प्रमाणित करते ये गैर सरकारी संगठन जहाँ एक और मानव के लिए अधिकारों की सार्थकता सिद्ध कर रहे है। वही दूसरी तरफ इनका इनके